साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 25-31 अक्टूबर 2021, वर्ष-7, अंक-30

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

शिवराज की घोषणा: दो मेगावॉट तक का सोलर पैनल लगाने बैंक से मिलेगा लोन

किसानों को 1540 करोड़ का 'सम्मान'

» मप्र में सिंचाई क्षमता साढ़े 7 लाख हे. से बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर हुई

» वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता करने का लक्ष्य

-शिवराज ने कहा-भगवान के बाद मेरे लिए श्रद्धा के केन्द्र हैं किसान

» प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से डाली राशि

» किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं आने देंगे

» पीएम किसान कल्याण और किसान की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध

» किसान अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाएं, सरकार सर प्लस बिजली खरीदेगी

» किसानों के हित के लिए सरकारी खजाने में धन की कोई कमी नहीं

» प्रदेश के अन्नदाता छह करोड़ मेट्रिक टन अनाज का उत्पादन कर रहे

» मध्यप्रदेश में एक नवम्बर से आरंभ होगा भू-अभिलेख शुद्धिकरण

» छिंदवाड़ा

» डीएपी खाद के विकल्प के रूप में एनपीके उर्वरक के उपयोग की सलाह

» किसानों के लिए इथनॉल पॉलिसी, खाद की कालाबाजारी करने वाले जाएंगे जेल

» कुछ दिन बाद फसल बीमा का पैसा भी किसानों के खातों में डाला जाएगा

» किसानों की मेहनत और योजनाओं से कृषि विकास की दर 18 प्रतिशत हुई

» किसानों के प्रयास से मध्यप्रदेश को सात बार मिला कृषि कर्मण अवॉर्ड

» प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसानों के खेतों तक पहुँचाया नर्मदा मैया का पानी

» कोयला महंगा होने के बावजूद किसान को सस्ती दरों पर दी बिजली

भोपाल, विशेष संवाददाता

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख किसान परिवार के खातों में किसान सम्मान निधि की 1540 करोड़ राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी। इसके बाद सीएम ने कहा कि बिजली का संकट पूरी दुनिया में है। कोयला महंगा होता जा रहा है। लेकिन किसानों को सस्ती और पर्याप्त बिजली देने के लिए बिजली कंपनियों को सब्सिडी दी है। कोयले का संकट पूरी दुनिया में अया है। अब हम बिजली के दूसरे स्त्रोत के बारे में सोच रहे हैं। धीर-धीरे सोलर से बिजली बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कोयले का विकल्प ढूढना है। सरकार नई योजना लेकर आ रही है। किसान यदि अपने खेतों में दो मेगावॉट बिजली के सोलर पैनल लगाता है तो बैंक से लोन मिलेगा। किसानों की जरूरत के बाद बची बिजली को सरकार तीन रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद लेगी। ओंकारेश्वर डेम के ऊपर भी सोलर पैनल लगाएंगे। सीएम ने यहां किसानों से संवाद भी किया। इसमें वे जिले शामिल नहीं हुए, जहां उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है।

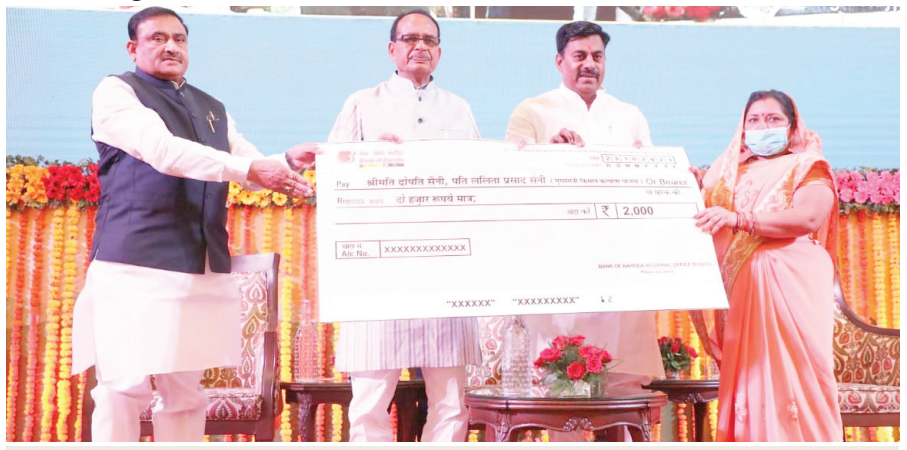

खाद के लिए रखें धैर्य

सीएम ने खाद की उपलब्धता के लिए किसानों को धैर्य रखने की बात कही। सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार के संपर्क में है। खाद की कमी नहीं आने देंगे। खाद की आपूर्ति अंतरर्राष्ट्रीय स्तर से होती है, इसलिए देरी हो जाती है। हम खाद की मॉनीटरिंग कर रहे है। किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की, काला बाजारी करने की कोशिश की या ब्लैक में बेचने की कोशिश की तो छोड़ेंगे नहीं। उन्हें जेल भेजा जाएगा। नंबर से अभियान चलाकर अविवादित खातों का निराकरण करेंगे। शुद्धिकरण भी करेंगे।

बरगी का पानी जाएगा सतना

खजाना खाली फिर भी पैसा दे रहे हैं। 2003 से पहले दो हजार करोड़ टन उत्पादन हो रहा था, जो अब बढ़कर छह हजार करोड़ हो गई। ये सिंचाई से संभव हुआ। हमने सिंचाई योजनाएं बनाई। निमाड़-मालवा में पठार पर नर्मदा का पानी पहुंचाना था। बरगी का पानी टनल के जरिए सतना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई योजना पर काम कर रहे हे। जहां भी पानी होगा, वहां रोकूंगा और किसानों को पानी दूंगा। 65 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है।

मिलेगी बिजली

कोयला महंगा हो रहा है बिजली खपत बढ़ रही है। मैंने तय किया किसानों को सस्ती बिजली दूंगा। इसके लिए सरकार को 21 हजार करोड़ रुपए देना पड़ता है। कोयला संकट पूरी दुनिया में आ रहा है। फिर भी मैं भरोसा दिला रहा हूं प्रदेश में बिजली संकट नहीं आने दूंगा। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराऊंगा। इथेनॉल बनाने के लिए हम योजना ला रहे हैं। अनाज से इथेनॉल बनाएंगे।

-राजधानी के 10 गांव में गोबर से बनाए जा रहे हैं सुगंधित दीये

अयोध्या और मथुरा जाएंगे 14 लाख 'राम नाम' दीये

भोपाल, विशेष संवाददाता

राजधानी से सटे 10 गांव में एक हजार महिलाएं 15 लाख दीये बनाने के काम में जोर-शोर से जुटी हैं। खास बात यह है कि ये दीये गोबर से बनाए जा रहे हैं, जो सुगंधित होंगे। हर दीये पर 'राम नाम' लिखा जा रहा है। इन दीपकों की खासियत यह भी होगी कि इन्हें नदियों में बहाने पर पानी प्रदूषण नहीं होगा। ये स्वत: पानी में घुल जाएंगे। दीये के साथ घी की बाती भी दी जा रही है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि स्व सहायता समूह के समर्थन ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन दीपकों में से 11 लाख अयोध्या और 3 लाख मथुरा के मंदिरों भेजे जाएंगे। दीये बनाने का ऑर्डर समूह की महिलाओं को जिला पंचायत के आजीविका मिशन के जरिए साईं माध्यम द्वारा दिया गया है। इन्हें बनाने के लिए जिस मटेरियल की जरूरत पड़ रही है, उसे जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन के अफसरों ने बताया कि पहली बार गोबर से दीये बना रहे हैं। दीवाली के लिए पांच लाख दीये बनाए जा रहे हैं।

सुगंधित पाउडर | दीये को बनाने में गोबर में गेहूं का आटा और मुलतानी मिट्टी भी मिलाई जा रही है। इसमें सुगंध के लिए एक पाउडर मिलाया जा रहा है। तीन हजार दीये बनाने के लिए गोबर से बने 40 कंडे, 6 किलो मुलतानी मिट्टी और 5 किलो आटे की जरूरत पड़ती है।

अयोध्या के भव्य दीपोत्सव में जाएंगे भोपाल के दीये | ये दीये अगले महीने अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव में भेजे जाएंगे। इसका आर्डर साईं माध्यम को मिला है। आजीविका मिशन की रेखा पांडे ने बताया कि शहर से 8 किमी दूर स्थित ईंटखेड़ी पंचायत, निपानिया सूखा से सटे 10 गांव की महिलाएं दीये बनाने के काम में लगी हुई हैं।

बनाए पांच लाख दीये

चार महीने में 5 लाख दीये बनाए गए हैं। प्रत्येक का 50 पैसे के हिसाब से भुगतान होगा। यानी तीन हजार दीये बनाने पर 1500 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार 3 हजार दीये की पैकेजिंग करने पर 1500 रुपए दिए जाएंगे। इनमें कलर करने पर 1500 रुपए और मिलेंगे। गौरतलब है कि मप्र में सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं। खासकर गाय। भोपाल में किया गया प्रयोग अगर प्रदेश भर के पशुपालक करें तो उनकी आय बढ़ जाएगी और वो आत्मनिर्भर होंगे। इस तरह के नवाचारों से बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा और धंधा भी शुरू हो जाएगा।

छिंदवाड़ा में सड़ गया 27 करोड़ का सरकारी गेहूं

संवाददाता, छिंदवाड़ा। साल 2020 में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदा गया करीब 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं सही रखरखाव न होने से सड़ गया। दरअसल, सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए 48 हजार मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण चौरई के चंदन वाड़ा में ओपन कैंप में किया गया था। इसकी देखरेख की पूरी जवाबदारी मार्कफेड को दी गई थी, लेकिन गौर किया जाए तो मार्कफेड के जिम्मेदार अधिकारियों ने गेहूं के भंडारण में व्यापक पैमाने पर लापरवाही की। लापरवाही के चलते यहां 47 हजार मीट्रिक टन गेहूं में से करीब 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं बारिश के पानी से बचाव न होने के कारण सड़ गया। यहां रखे बोरों में से गेहूं के दाने उग आए हैं। वहीं, कुछ बुरे ऐसे भी है, जिसमें भरा गेहूं काला हो गया है। यह अनाज बदबू मारने लगा है। अनुमान के मुताबिक सड़े हुए गेहूं की कीमत करीब 27 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

» लापरवाही:14 हजार मीट्रिक टन गेहूं हो गया खराब

» -चौरई के ओपन कैम्प में दो साल से रखा था गेहूं

2300 रुपए में उद्यानिकी विभाग ने खरीदा 1100 का बीज

ईओडब्ल्यू की जांच शुरू

मध्यप्रदेश में दो करोड़ का प्याज घोटाला

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में प्याज घोटाले की जांच अब ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी है। इस जांच की रडार पर उद्यानिकी विभाग के कमिश्नर आ गए हैं। विभाग के संबंधित और जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस भेजकर जबाव तलब किया जा रहा है। आरोप है कि अप्रमाणित बीज खरीद कर सरकार को आर्थिक नुकसान और घोटाला किया गया। प्रमाणित बीज के जो रेट तय किए गए थे उससे भी अधिक दर पर विभाग ने अप्रमाणित बीज खरीदा। राज्य शासन ने प्याज के उस बीज को इसलिए प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि इससे पैदावार कम होती थी। इसकी जगह पर अब प्रमाणित हाइब्रिड बीज को अनुमति दी गई है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर विभाग ने घोटाला करते हुए अप्रमाणित बीज की खरीदा। दरअसलख राज्य शासन ने उद्यानिकी नर्सरियों पर प्रमाणित बीजों की बिक्री दर 1100 रुपए प्रति किलो तय की थी। इसके बाद भी उद्यानिकी विभाग ने अप्रमाणित खरीफ प्याज बीज दोगुने से भी ज्यादा दाम 2300 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीद लिया। बीज एमपी एग्रो की जगह दूसरी संस्थाओं से खरीदा गया।

खरीद लिया 90 क्विंटल प्याज

राष्ट्रीय बागवानी मिशन में इसी साल पहली बार खरीफ प्याज को शामिल किया गया है। इसके बाद विभाग ने दो करोड़ रुपए में 90 क्विटल प्याज बीज को खरीद लिया। उद्यानिकी को एमआईडीएच योजना में संकर सब्जी बीज के नाम पर केन्द्र सरकार से दो करोड़ रुपए मिले थे। इस राशि से नियमों को ताक पर रखकर निम्न गुणवत्ता के अप्रमाणित प्याज बीज की किस्म एग्री फाउंड डार्क रेड की खरीदी कर ली गई।

तीन हजार किसान जुटे: तीन हजार हेक्टेयर में हो रहा उत्पादन

श्योपुर में सेलम हल्दी से संवर रहा किसानों का भविष्य

जिले में इस साल करीब 3 हजार हेक्टेयर में हल्दी की खेती हो रही है। आजीविका मिशन के माध्यम से करहाल में हल्दी प्रोसिंग यूनिट तैयार की जा रही है। इसके लिए मशीन भी आ चुकी हैं। यहां हल्दी को सूखाने से लेकर पैकिंग आदि भी की जाएगी।

शिवम वर्मा, कलेक्टर, श्योपुर

करहाल जनपद के पास आजीविका भवन में 98 लाख की लागत से प्रोसेसिंग यूनिट तैयार की जा रही है। आजीविका प्रोड्यूसर कंपनी ने भोपाल की एक्सिस डवलपमेंट एजेंसी से भी अनुबंध किया है। एजेंसी हल्दी को ब्रांड बनाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट करने के साथ ही आईएसआई मार्का दिलाने के लिए भी काम करेगी।

डॉ. एसके मुदगल, डीपीएम, आजीविका मिशन श्योपुर

-मप्र स्थापना दिवस पर हल्दी प्रोसिंग यूनिट शुरू हो जाएगी

श्योपुर। संवाददाता

आदिवासी बहुल श्योपुर जिले की हल्दी जल्द ही अब दूर-दूर तक अपनी सुनहरी चमक बिखेरगी। हल्दी का रकबा बढ़ने के साथ ही मप्र ग्रामीण आजीविका मिशन समूह से जुड़ी महिलाएं कराहल में यूनिट लगाने जा रही हैं। हल्दी सूखाने, पीसने से लेकर पैकेजिंग करने वाली मशीन आ गई है। अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो मप्र स्थापना दिवस पर हल्दी प्रोसिंग यूनिट शुरू हो जाएगी। प्रशासन से भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आदिवासी ब्लॉक कराहल के बरगवां, दुबड़ी, बमौरी, गड़ला, चितारा सहित अन्य गांवों के किसान इन दिनों हल्दी की खेती कर रहे हैं। इस हल्दी में कुर्कमिन या करक्यूमिंन औषधीय तत्व पाया जाता है। करीब 6 महीने पहले पतंजलि, मुनीम जी मसाले और डाबर जैसी कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी आजीविका प्रोड्यूसर कंपनी से इस हल्दी को खरीदने के लिए संपर्क किया था। उस समय कंपनियों की डिमांड थी, कि उन्हें हल्दी पीसकर दी जाए। यही वजह है, कि समूह की महिलाएं अब हल्दी प्रोसिंग यूनिट शुरू करने जा रही है।

तीन हजार किसान कर रहे हल्दी की खेती

2012 में आदिवासी ब्लॉक बरगवां संकुल के ग्राम दुबड़ी, बमौरी, गड़ला, बगरवां, चितारा, कांकरा, डूंडीखेड़ा, सारनअहिरवानी, अगरा, मदनपुर, पाली, हीरापुर 40 किसानों ने 15 एकड़ में खेती शुरू की। 450 क्विंटल हल्दी का उत्पादन हुआ। किसानों ने हल्दी को मसालों के साथ ही अन्य किसानों को बीच बेचा, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। 2019-20 में 150 किसानों ने 7500 क्विंटल हल्दी का उत्पादन किया। इसका उत्पादन एक हेक्टेयर में 45-50 क्विंटल होता है। प्रति हेक्टेयर में किसान को 40 से 50 हजार रुपए का शुद्ध हुआ था। इसलिए इस साल करीब 3000 हजार किसानों ने 3 हजार हेक्टेयर में हल्दी का उत्पादन किया है।

सेलम हल्दी का उत्पादन

श्योपुर जिले में किसान सेलम हल्दी का उत्पादन कर रहे है सेलम हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व सबसे महत्वपूर्ण और एक्टिव सामग्री माना जाता है, जो हल्दी के चमकदार पीले रंग और तीखी खुशबू का कारण है। करक्यूमिन शरीर में फंगल का जन्म नहीं होने देता है और साथ ही टिशू में सूजन को भी कम करने में मदद करता है।

मध्यप्रदेश में तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी कर ली है। एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर जिलों में मैदानी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नब्ज टटोली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण है। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव कराने में अब कोई परेशानी नहीं है। हमारे स्तर पर तैयारी हो चुकी हैं। चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे। सभी जिले मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराने के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की सूची तत्काल भेजें। जिन मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मार्ग ठीक नहीं है, उन्हें दुरुस्त कराया जाए।

राज्य चुनाव आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा

सभी पंचायतों का होगा चुनाव

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश की सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिनका मार्च 2022 तक पूरा हो रहा है, वहां चुनाव करवाया जाएगा। मतदान तीन चरणों में होगा। सेक्टर और जोनल अधिकारी की नियुक्ति कर उन्हें निर्वाचन के दौरान विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी शक्तियां देने का प्रस्ताव शीघ्र भेजें। जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन-पत्र जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्यों के ब्लॉक मुख्यालय और सरपंच और पंच के ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर लिए जाएंगे।

किसान मक्का की फसल को धूप में सुखाकर लाएं मंडी

भोपाल। मध्यप्रदेश की मंडियों में खरीफ सीजन प्रारंभ हो गया है। मंडियों में मक्का की आवक किसान किसानों द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा सभी किसानों को सूचित किया गया है कि वो मक्का की फसल मंडियों में विक्रय के लिए लाने से पहले उसे अच्छे से धुप में सुखा लें जिससे उनको मक्का के उचित मूल्य मंडियों में विक्रय के समय मिलेगे। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल ने बताया कि वर्तमान में मंडियों में जो मक्का आ रही है, उसमे 16 प्रतिश से 22 प्रतिश तक नमी है। इस कारण किसानों को मक्का का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नहीं मिल पा रहा है। नरवाल द्वारा समस्त मंडी सचिवों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं कि वह अपने मंडी क्षेत्र के किसानों को अवगत कराएं कि किसान मक्का की फसल धूप दिखाकर अच्छे से सुखाकर मंडी में विक्रय के लिए लाएं। ताकि किसानों को मक्का की फसल का विक्रय के बाद उचित दाम मिल सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि उक्त सूचना मंडियों में लगे ध्वनिविस्तारक यंत्र से निरंतर करें और अपने क्षेत्रों में मुनादी कराकर भी किसान भाइयों को सूचना प्रसारित करें। किसानों को मंडी में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसका पूरा-पूरा ध्यान मंडी प्रशासन रखे।

आएंगे अच्छे दिन किसानों को मिलेगी पांच गुना ज्यादा पैदावार, बढ़ जाएगी आय

एरोपॉनिक तकनीक अब हवा में उगेगा आलू

भोपाल। संवाददाता

जमीन के अंदर आलू की खेती होते सबने देखी होगी। अब एरोपॉनिक तकनीक से हवा में भी आलू की खेती की जा सकेगी, जिसमें पांच गुना ज्यादा पैदावार भी होगी। देश में यह एक क्रांतिकारी प्रयास है। इस तकनीक की मदद से आलू जमीन में नहीं, बल्कि हवा में उगाया जा रहा है। इस तकनीक से आलू उगाने पर किसानों को पांच गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है। इसके साथ ही आलू को सड़ने और खोदते समय होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। इससे किसानों की आय भी बढ़ जाएगी।

क्या है एरोपॉनिक तकनीक

यह एक ऐसी तकनीक है, जिसके तहत आलू के पौधों की जड़ें हवा में लटकती हैं। इससे पौधों को पोषण मिलता है। इस कारण मिट्टी और जमीन, दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तकनीक से आलू की उपज क्षमता 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। इस तकनीक से आलू की खेती करने के लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और आलू प्रोद्योगिकी केंद्र करनाल के बीच एक एमओयू भी हुआ है।

क्या होगा फायदा | इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आलू को जमीन और हवा, दोनों में आलू उगाया जा सकता है। इस तकनीक से आलू उगाने का प्रयोग हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में हुआ। विशेषज्ञों की मानें, तो आलू की उपज बिना जमीन और मिट्टी के ही खेती करके 10 गुना बढ़ाई जा सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल व्यापक तौर शुरू हो सकता है। इस तकनीक से खेती करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

जमीन की नहीं पड़ेगी जरूरत

हवा में आलू उगाने वाली एरोपॉनिक तकनीक किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इस तकनीक से कम लागत में बंपर उपज प्राप्त की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकनीक से आलू की खेती करने के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए किसानों की अच्छी आमदनी हो जाती है।
जानकारी के लिए बता दें कि एरोपॉनिक तकनीक द्वारा बिना मिट्टी व जमीन के आलू उगाए जा रहे हैं। इसमें एक पौधा 40 से 60 छोटे आलू तक दे रहा है। इन्हें खेत में बीज के तौर पर रोपित किया जा रहा है। इससे किसानों को काफी अच्छा लाभ मिल रहा है।

वाराणसी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन का पौधा ब्रिमेटो

अब एक ही पौधे में लगेंगे टमाटर-बैंगन के फल

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने किया कारनामा

भोपाल। संवाददाता

वाराणसी के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसा पौधा तैयार किया है, जिसमें टमाटर और बैंगन के फल एक ही पौधे में लगेंगे।
वैज्ञानिकों ने पौधों की ग्राफ्टिंग के माध्यम से कलम तैयार कि जिससे बैंगन और टमाटर एक ही पौधे में उगाए जा सकेंगे। इस उपलब्धि से कम जगह में ज्यादा पैदावार पाई जा सकेगी। इसे अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में छोटे स्थानों में अधिक सब्जियों के उत्पादन में सफलता माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रिमेटो के हर पौधे से करीब 3-4 किलो बैंगन और 2-3 किलो टमाटर मिल सकेगा। इससे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पोमेटो नामक पौधे की क़लम तैयार की थी। उस पौधे से आलू और टमाटर की मिश्रित उपज मिलती है। इन फसलों को लेकर सब्जी उत्पादकों में खासा उत्साह है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे इनके न्यूट्रीशन में कोई कमी नहीं आएगी। इनके उत्पादन में लगने वाली लागत में कमी आएगी। सब्जियों की खेती में लगने वाली जगह, खाद, पानी के साथ देखभाल में भी कम

समय लगेगा। ब्रिमेटो तैयार करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि बैंगन का अंकुर 25-30 दिन और टमाटर का अंकुर 22-25 दिन पुराना था। जिसे ग्राफ्टिंग यानी कलम बांधने की तकनीक से विकसित किया गया। इसमें पौधे के टिश्यू को रीबर्थ के माध्यम से पौधों के हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एक पौधे की कलम को वी शेप में और दूसरे को टी शेप में कट किया जाता है। फिर उन्हें एक आपस में तने के अंदर या ऊपर, जड़, या टहनी के साथ जोड़ दिया जाता है। वैज्ञानिकों की मानें तो जो हिस्सा जड़ उपलब्ध कराता है उसे स्टॉक कहते हैं और जुड़े हुए हिस्से को कलम कहा जाता है। ब्रिमेटो को एक या कई कलम तैयार करके विकसित किया गया है। इसमें एक ही पौधे के परिवार के दो या उससे अधिक अंकुरों की कलम एक साथ तैयार किया गया है, जिससे एक ही पौधे से एक से ज़ूयादा सब्जियां हासिल की जा सकती हैं। ब्रिमेटो के पेरेंट प्लांट्स एक बढ़े हुए बैंगन हाईब्रिड होते हैं, जिन्हें काशी संदेश कहा जाता है। वहीं टमाटर की एक सुधरी हुई किस्म जिसे काशी अमन कहते हैं। इन दोनों की कलम आईसी 111056 कही जाने वाली बैंगन रूट स्टॉक में लगाई गई थी।

कलम वाली तकनीक फूलों और फलों तक थी सीमित

सब्जियों से पहले यह कलम वाली तकनीक फूलों और फलों तक सीमित थी। अब इसे सब्ज़ियों पर भी लागू किया गया है। माना जा रहा है कि पोषण सुरक्षा के मामले में भी ब्रिमेटो बहुत उपयोगी साबित होगा। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर, घरेलू पोषण सुनिश्चित करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इससे बैंगन के कसैलेपन में भी कमी आती है और फसलों के अंदर रसायन की मौजूदगी घटती है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विवि हिसार के वैज्ञानिकों की खोज

खेती की लागत कम करेगा ई-ट्रैक्टर

भोपाल। संवाददात

लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों से कृषि लागत में भी इजाफा हो रहा है। इसे कम करने के लिए अब इलेक्ट्रिक एवं बैटरी से चलने वाले कृषि यंत्रों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने बैटरी से चलने वाला ई-ट्रैक्टर को तैयार किया है। यह टैक्टर 16.2 किलोवाट की बैटरी से चलता है और डीजल ट्रैक्टर की तुलना में इसकी संचालन लागत बहुत कम है।

ई-ट्रैक्टर के प्रयोग से किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। कुलपति प्रोफेसर बीआर काम्बोज ने बताया कि यह ई-ट्रैक्टर 23.17 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है व 1.5 टन वजन के ट्रेलर के साथ 80 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यह अनुसंधान उपलब्धि कृषि मशीनरी और फार्म इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक एवं वर्तमान निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार डॉ. मुकेश जैन के मार्गदर्शन में प्राप्त की गई है।

ट्रैक्टर की खासियत

ई-ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 16.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया। इस बैटरी को 09 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान 19 से 20 यूनिट बिजली की खपत होती है। उनके अनुसार ट्रैक्टर 1.5 टन वजन के ट्रेलर के साथ 80 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का भी विकल्प उपलब्ध है, जिसकी मदद से ट्रैक्टर की बैटरी महज 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। इसमें शानदार 77 प्रतिशत का ड्राबार पुल है, यानि ट्रैक्टर 770 किलो वजन खींचने में सक्षम है। ट्रैक्टर में कंपन और शोर की बात की जाए तो इसमें 52 प्रतिशत कम्पन और 20.52 प्रतिशत शोर बीआईएस कोड की अधिकतम अनुमेय सीमा से कम पाया गया। ट्रैक्टर में ऑपरेटर के पास इंजन ना होने के कारण तपिश भी पैदा नही होती जो ऑपरेटर के लिए बिलकुल आरामदायक साबित होगा।

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की लागत

डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए यह ट्रैक्टर किसानों के लिए काफ़ी किफायती साबित होगा जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के संचालन की लागत के हिसाब से यह डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले में 32 प्रतिशत और 25.72 प्रतिशत तक सस्ता है। बैटरी से चलने वाले ट्रैक्टर की कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए आएगी। इसके साथ ही समान हार्स पावर वाले डीजल ट्रैक्टर की कीमत 4.50 लाख रुपए है।

श्वेतक्रांति के विकास की संभावनाएं

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में टॉप पर है। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में अकेले भारत का हिस्सा 25 प्रतिशत के लगभग है। इसके बाद विश्व के टॉप पांच देशों की सूची में यूएसए 98.72 मिलियन टन, पाकिस्तान 45.79 मिलियन टन, चीन 35.60 मिलियन टन, ब्राजील 34.11 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, जहां 30519 हजार टन रिकॉर्ड दुग्ध उत्पादन हो रहा है। बावजूद इसके आबादी में बड़ा राज्य होने के कारण वहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 371 ग्राम ही है। राजस्थान में उत्पादन 23668 हजार टन एवं उपलब्धता 870 ग्राम, मध्य प्रदेश में उत्पादन 15911 हजार टन तथा उपलब्धता 538 ग्राम है।

आकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये सभी देश भारत से दुग्ध उत्पादन के मामले में काफी पीछे खड़े दिखाई देते हैं। आने वाले वर्षों में भारत में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी की काफी संभावनाएं विद्यमान हैं। क्योंकि पशुधन की संख्या के मुकाबले देश में अन्य दुग्ध उत्पादक देशों की तुलना में अभी भी प्रति दुधारू पशु दुग्ध उत्पादकता काफी कम है। आजादी के इतने वर्षों के उपरांत श्वेत क्रांति के जोरदार आगाज के बाद भी हमारी भारतीय गाय के एक ब्यांत का औसत दुग्ध उत्पादन पाकिस्तान जैसे देश के मुकाबले आधा है। आंकड़ों के अनुसार भारत में गाय का एक ब्यांत का औसत दुग्ध उत्पादन 1100 लीटर, पाकिस्तान का 2200 लीटर, यूएसए का 9000 लीटर तथा इजराइल का 11000 लीटर तक है। भारतीय श्वेत क्रांति की यह एक ऐसी सच्चाई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। संपूर्ण विश्व में भारत सर्वाधिक दूध पैदा करने वाले देश के रूप में पहचान कायम कर चुका है। देश में आज 200 मिलियन टन के लगभग दुग्ध उत्पादन हो रहा है, बावजूद इसके अभी भी दुग्ध उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं। देश के कुछ एक राज्यों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो बाकी अधिकांश राज्य दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अभी भी काफी पीछे हैं। इन राज्यों में दुग्ध उत्पादन कम होने के पीछे प्रमुख वजहों में पशुओं की उन्नत नस्ल का अभाव, हरे चारे की कमी, अच्छी गुणवत्ता का सूखा चारा नहीं मिलना, दुग्ध उत्पादन के आधार पर संतुलित आहार नहीं मिलना, बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाओं की कमी प्रमुख समस्याओं में शामिल है। जिसे नस्ल सुधार, अच्छी खिलाई-पिलाई, हरे चारे की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करके अधिकतम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। देश के गाय-भैंस पालन करने वाले अधिकांश राज्यों में देशी और दोगली नस्ल की गाय-भैसों का नस्ल सुधार किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। गाय-भैस की नस्ल सुधार के बिना देश में दुग्ध उत्पादन को अधिकतम ऊचांई तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। हांलाकि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश ने बहुत लंबा रास्ता तक किया है। विगत छह सालों के दरम्यांन भारत में 35.61 प्रतिशत की दर से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में देश में 146.3 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन हो रहा था, जो कि वर्ष 2019-20 में बढ़कर रिकॉर्ड स्तर 198.4 मिलियन टन तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, बल्कि साल दर साल में इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हर वर्ष दुग्ध उत्पादन में लगभग पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ ही प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश के पिछले तीस सालों के दुग्ध उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वर्ष 1991-92 में 55.6 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रति व्यक्ति उपलब्धता

178 ग्राम थी। दुग्ध उत्पादन वर्ष 2018-19 में बढ़कर 187.7 मिलियन टन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम तक पहुंच गई है। देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, जहां 30519 हजार टन रिकॉर्ड दुग्ध उत्पादन हो रहा है। बावजूद इसके आबादी में बड़ा राज्य होने के कारण वहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 371 ग्राम ही है। इसी प्रकार से राजस्थान में उत्पादन 23668 हजार टन एवं उपलब्धता 870 ग्राम, मध्यप्रदेश में उत्पादन 15911 हजार टन तथा उपलब्धता 538 ग्राम है। जबकि देश के अन्य प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्रमश: 12599, 10726, 11655, 14493 एंव 15044 हजार टन उत्पादित हो रहा है। वहीं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता के मामले में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश में क्रमश: 1181, 1087, 266, 626 एवं 623 ग्राम है। भारत दुग्ध उत्पादन में भले ही अग्रणी देश है। बावजूद इसके अभी भी दुग्ध उत्पादन बढ़ाए जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। भारत के नाम जिस प्रकार से विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड है। उसी प्रकार से देश में विश्व की सर्वाधिक दुधारू पशुओं की संख्या का भी रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन पशुओं की यह संख्या उत्पादक कम अनउत्पादक ज्यादा है। वर्तमान में देश में 192.5 मिलियन गाय, 109.9 मिलियन भैस, 74.3 मिलियन भेड़ तथा 148.9 मिलियन बकरी की संख्या है। जिसमें से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भैस से लगभग 55 प्रतिशत तक उत्पादित किया जाता है। जबकि गाय से 42 प्रतिशत तथा बकरी से 3 प्रतिशत तक दुग्ध उत्पादन प्राप्त होता है। पशुधन की विभिन्न प्रजातियों की आबादी में परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 1951 में गायों की आबादी 2.2 प्रतिशत से गिरकर 0.8 प्रतिशत तक हो गई। इसी प्रकार से भैंस की अबादी 1951 में 3.5 प्रतिशत से गिरकर 1.1 प्रतिशत तक आ गई है। तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का रुझान पशुपालन की तरफ कम हो रहा है, जिसे पुन: बढ़ाने की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2019-20 के आकड़ों पर नजर डाली जाये तो देश की कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में पशुपालन एवं डेयरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। देश की वर्ष 2018-19 की कुल जीडीपी 1,71,39,962 करोड़ रुपए थी जिसमें कृषि एवं कृषि से जुड़े व्यवसायों से 29,22,846 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। जिसमें पशुपालन एवं डेयरी सेक्टर का योगदान 8,71,884 करोड़ रुपए था। इस प्रकार से कुल जीडीपी में कृषि एवं कृषि से जुड़े सभी सैक्टरों से 17.1 प्रतिशत की प्राप्ति हो रही थी। जिसमें अकेले पशुपालन एवं डेयरी सैक्टर का योगदान 5.1 प्रतिशत था। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कृषि में पशुपालन एवं डेयरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। आगामी परिदृश्य को देखा जाए तो आने वाले वर्षों में पशुपालन एवं डेयरी सेक्टर आज जिस गति से वृद्धि कर कर रहा है। वह आगे भी इसी प्रकार से जारी रहने की पूरी संभावना है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की दैनिक जरूरतों को देखते हुए भविष्य में भी इनकी मांग बढ़ती रहेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय के विकास को और अधिक गति से बढ़ाना होगा।

कम्पोस्ट खाद-किसानों के लिए संजीवनी

आशुतोष मिश्र
कृषि संकाय, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि, चित्रकूट

पौधों के अवशेष पदार्थों पशुओं का बचा हुआ चारा, बगीचों की पत्तियां, फलों के छिलकों, कूड़ा करकट, घरों से निकला हुआ कचरा, जानवरों और मनूष्यों के मल-मूत्र आदि पदार्थों को वैक्टीरिया व फंजाई द्वारा विशेष दशाओं में विच्छेदन से बना हुआ पदार्थ कम्पोस्ट कहलाता है। कम्पोस्ट खाद तैयार करने की क्रिया को ही कम्पोस्टिगं कहते हैं। कम्पोस्टिगं एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें वायु जीवी तथा अवायु जीवी दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को विच्छेदन करके पौधों के अवशेष पदार्थो का कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात कम करते हैं।

कम्पोस्ट का यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है। इस श्रेणी के पदार्थों में फार्म का कूड़ा करकट सभी फसलों के अवशेष, जल कुंभी, ढेंचा, गलियों का कूड़ा करकट आदि प्रमुख के पदार्थ मुख्य हैं। कार्बन-नाइट्रोजन अनुयात 30-35 के मध्य होना चाहिए। जिससे विघटन की क्रिया अच्छी होती है। कम्पोस्टिंग प्रक्रिया में मुख्य प्रारंभ का प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का गोबर मूत्र, विष्ठा, सीवेज स्लज, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट तथा एडको पाउडर आदि। वायुवीय विघटन के लिए 50 से 60 प्रतिशत नमी आवशयक है। इससे कम होने पर जीवाणुओं की क्रिया धीमी हो जाएगी। इससे अधिक होने पर (80 से 90 प्रतिशत) होने पर आक्सीजन के पानी में घुलने से विघटन अवायवीय होकर धीमा हो जाएगा। अत: विघटन के दौरान उपयुक्त नमी बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। कम्पोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान आरंभ में 20 से 25 डिग्री तापमान होता है, जो बढ़कर 50 से 60 डिग्री तक जाता है, और अन्त में कम होकर पुन: सामान्य हो जाता है। उच्च तापमान पर खरपतवार के बीच तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। विघटन की क्रिया तीव्रता से होती है। अत: कम्पोस्टिंग के दौरान तापमान बढ़ना आवश्यक है। यदि तापमान नहीं बढ़ता है तो विघटन की प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। यह समझना चाहिए एवं आवश्यक सुधार करना चाहिए। कम्पोस्ट का पीएच. शुरुआत में अम्लीय (4 से 6) होता है, व विघटन के बाद पीएच 8 से 9 हो जाता है। पीएच का बढ़ना विघटन पूर्ण होने का निर्देशांक है। वायुवीय विघटन के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन मिलना आवश्यक होता है। अत: कम्पोस्ट के गड्ढे ढेर अथवा टैंक की गहराई ती फीट से अधिक व चौड़ाई 5 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। ताकि कार्बनिक पदार्थ में चारों तरफ से हवा का वहन हो सके। कम्पोस्ट के टैंक, गड्ढे अथवा ढेर बनाने की जगह हमेशा पेड़ की छांव में होना चाहिए एवं स्थान ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि वर्षा का पानी एकल न हो सके। कम्पोस्ट बनाने की जगह पानी के स्रोत के पास होनी चाहिए, क्योंकि कम्पोस्ट बनाने के लिए काफी मात्रा में बार-बार पानी की आवयकता पड़ती है। कम्पोस्ट एक ही प्रकार के कचरे से नहीं वरन अलग-अलग प्रकार के सूखे एवं हरे कचरे को मिश्रित करके बनाना चाहिए। कम्पोस्ट का ढेर टैंक अथवा गड्ढा 1 से 2 दिन में पूर्ण भरकर सील कर देना चाहिए अन्यथा जीवाणुओं की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं होती। गर्मी के दिनों में कम्पोस्ट गड्ढो में व बरसात के दिनों में जमीन के ऊपर टैंक अथवा ढेर बनाना चाहिए। वाष्पीकरण को रोकने के लिए कम्पोस्ट के टैंक पर आच्छादन करना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान समय पशुओं की संख्या में कमी के कारण गोबर की कमी को देखते हुए हमारे देश के एक सामाजिक कार्यकर्ता एक ऐसी विधि की खोज की जिसके द्वारा 1 किग्रा गोबर से 15 किग्रा कम्पोस्ट तैयार कर सकते हैं। जिसके विषय में विस्तृत से वर्णन करते हैं। चमत्कारिक कम्पोस्ट बनाने की नाडेप विधि का विकास भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता नारायण देव रावं पंडरी पांडे के द्वारा किया गया था। पंडरी पांडे नाडेप काका के नाम से भी लोकप्रिय है। इस विधि का प्रसार पूरे भारत में होता जा रहा है। इस पद्धति में नाडेप टैंक कम्पोस्ट बनाया जाता है। नाडेप कम्पोस्ट टैंक का आभार 12 फीट लम्बा, 5 फीट चौडाई, 3 फीट ऊंचाई का बनाया जाता है, जिससे आसानी से सारी प्रक्रिया किया जा सके यह टैंक ईट व सीमेंट से बनाया जाता है। टैंक के चारों दीवार, ऊंचाई पर 9 इंच के अंतर से 6 इंच के छिद्र छोड़े जाते हैं। ताकि हवा का वहन ठीक प्रकार से हो सके। ईंट की जुड़ाई मिट्टी अथवा सीमेंट से की जा सकती है। किन्तु टैंक की पूरी सत्ह पर सीमेंट व रेत की पक्की लाइनिंग देना आवश्यक है, ताकि टैंक मजबूत बने। नाडेप टैंक बनाने में लगभग 5 हजार रुपए तक खर्च आता है।

नीमच ब्रिगेडः जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ दिए

घनश्याम सक्सेना, वन विशेषज्ञ

क्या 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मध्यप्रदेश का निर्णायक योगदान था, क्या अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाली नीमच ब्रिगेड की जय-यात्रा ठेठ दिल्ली तक पहुंच गई थी, क्या जॉन निकल्सन जैसे ब्रिटिश जनरल को नीमच ब्रिगेड के गोले ने मर्मांतक घाव पहुंचाकर निपटा दिया था और क्या नीमच ब्रिगेड के प्रबुद्ध सेनापति सिरधारी सिंह ने बरेली की विद्रोही सेना के सिपहसालार बख्त खान और नसीराबाद-फौज के सेनापति भगीरथ मिश्रा के साथ मिलकर बहादुरशाह जफर की सूफी हुकूमत को संवैधानिक राजतंत्र में बदलने की भावभूमि तैयार कर दी थी। ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिन पर शोध-प्रयासों को केन्द्रित किए बगैर 1857 के स्वाधीनता संग्राम में मध्यप्रदेश का निर्णायक योगदान अपेक्षाकृत अल्पज्ञात ही रहेगा। नीमच ब्रिगेड का योगदान 1857 को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचा सकता था बशर्ते कि दिल्ली में कुछ आंतरिक तत्व गद्दारी न करते। 11 मई, 1857 को स्वाधीनता के दीवानों ने देश को पराधीन बनाने वाली कंपनी सरकार और उनके ब्रिटिश कारिंदों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाया। इसके ठीक तीन हफ्ते बाद नीमच में स्थित समूची फौजी ब्रिगेड ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का ऐलान कर दिया। नीमच, ब्रिटिश फौजी ताकत का एक प्रमुख केन्द्र था जहां से पश्चिमी और मध्यभारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता का वर्चस्व सुनिश्चित किया जाता था। यहां एक विशाल फौजी छावनी थी, जिसे नीमच ब्रिगेड कहा जाता था। तीन जून को इस समूची ब्रिगेड ने स्वयं को कम्पनी सरकार के प्रति वफादारी की शपथ से मुक्त करके अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़कर देश को आजाद करने का बीड़ा उठाया। यह ब्रिगेड कितनी विशाल थी और 1857 के स्वाधीनता संग्राम में इसका क्या महत्व था इसका पता शायद कभी न चलता यदि आरजी विलबर फोर्स ने सन् 1894 में लंदन में प्रकाशित अपनी पुस्तक अनरिकार्डेड चेप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी में इसका विस्तृत उल्लेख न किया होता। विलबर फोर्स लिखते हैं-नीमच ब्रिगेड हजारों सैनिकों, दस फील्ड तोपों और तीन मोर्टारों सहित दिल्ली पहुंच गई और रिज स्थित हमारी छावनी पर उसने भीषण हमला बोला। चिंतनीय है कि स्वयं ब्रिटिश लेखकों ने 1857 के इन अपेक्षाकृत अल्पज्ञात अध्यायों पर जितना गहन शोध किया है उतनी खोजबीन स्वयं स्वदेशी इतिहासज्ञों ने शायद ही किया हो। एरिक स्टोक्स ने सन् 1895 में आक्सफोर्ड से प्रकाशित अपनी पुस्तक द पीजेन्ट आर्मड द इंडियन रिकोल्ट ऑफ 1857 फीसदी में तीन रहस्योद्घाटन किए।

नई अफीम नीति के खिलाफ किसानों का विरोध

मंदसौर के काश्तकारों को रास नहीं आ रही अफीम नीति

गौरव तिवारी, मंदसौर

मंदसौर में अफीम नीति के खिलाफ बही चौपाटी पर किसान धरना-प्रदर्शन करेंगे। किसानों का कहना है कि घोषित की गई नई अफीम नीति किसानों के हित में नहीं हैं। किसान संगठन ने मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता पर नए लाइसेंस देने का वादा खिलाफ के आरोप लगाए हैं। नई अफीम नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने से किसानों में इस नीति को लेकर भारी आक्रोश है। किसानों को सांसद ने अच्छी अफीम नीति का भरोसा दिया था, लेकिन किसानों को निराशा ही हाथ लगी। न तो नीति किसानों के हित में आई, न ही अफीम के भाव में वृद्धि की गई। अफीम कास्तकार संगठन के अमृतराम पाटीदार ने बताया कि नीमच नारकोटिक्स विभाग के समक्ष प्रभावी धरना-प्रदर्शन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो,मल्हारगढ़ तहसील के बही चौपाटी पर धरना-प्रदर्शन किया आएगा। इस दौरान कलेक्टर को केन्द्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन देकर के नीति में परिवर्तन की उच्चस्तर पर मांग की।

किसानों की मांग

किसानों की मांग है कि इस साल 3.00 मार्फिन पर लाइसेंस दिए जाएं। 1990 से अब तक कम औसत में कटे पट्टे बहाल किए जाएं। घटिया पट्टे को तुरंत जारी किया जाए और तौल केंद्र की रिपोर्ट को ही अंतिम रिपोर्ट मानी जाए। 2013-14 में बेमौसम बरसात और शीतलहर से कटे हुए पट्टे दिए जाए। प्रत्येक किसान को 10-10 आरी के नए पट्टे दिए जाएं। अफीम का भाव 10 हजार रुपए प्रति किलो किया जाए। अफीम की फसल को भी फसल बीमा के दायरे में रखा जाए तथा सीएसपी पद्धति को पूरी तरह समाप्त किया जाए।

तीन खंडो में बांटा जा रहा लाइसेंस

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की जारी हुई अफीम नीति के बाद जिले में पात्र किसानों को पट्टा (लायसेंस) देने कार्य शुरू हो गया है। जिले के अफीम काश्तकारों को तीन खंडों में बांटा गया है। इन तीनों खंडों में मार्फिन की मात्रा पूरी करने वाले किसानों को पट्टा दिया जा रहा है। पट्टा मिलने के बाद किसान अफीम की बोवनी कर पाएंगे। 4.2 से 5 तक मार्फिन देने वाले किसानों को 6 ऑरी का पट्टा दिया जाएगा। तो 5 से 5.9 मार्फिन देने वालों को 10 ऑरी और 5.9 से अधिक मार्फिन देने वालों को 12 ऑरी का पट्टा दिया जाएगा।

नीति बन गई, नियम किसी को पता नहीं

जिले में बेठे अधिकारियों से जब बात की तो पता चला कि जारी की गई अफीम नीति में नियम तो बन गया, लेकिन यह किस तरह से होंगे। इसके क्या मापदंड हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अधिकारियों के अनुसार उन्हें नहीं पता कि खेत मे खड़ी अफीम की फसल से डोडे सरकारी अनुबंध के तहत कोई निजी कंपनी लेगी या नार्कोटिक्स विभाग। सीपीएस के अनुसार क्या मापदडुड होंगे, डोडों को कौन खरीदेगा। डोडों को किस स्थिति में काटा जाएगा। किसानों को कितना लाभ मिलेगा जैसे कई सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। इन्हीं सवालों के वजह से किसानों के बीच भी असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल सरकार ने कम औसत पर मार्फिन देने वाले किसानों को सीपीएस पद्धति से 6 आरी के पट्टे देगी। इसके लिए 8 से 12 नवम्बर की तारीख तय की गई है।

सीपीएस पद्धति के तहत मिलेगा लायसेंस

जिन किसानों की औसत अफीम में 3.7 से 4.2 तक मार्फिन पाई गई है उन्हें भी सरकार ने 6 आरी के पट्टे की पात्रता में रखा है । इन्हें भी अफीम पट्टे दिए जाएंगे बशर्ते अफीम का उत्पादन (सीपीएस) पद्धति के अनुसार करना होगा।

क्या है सीपीएस पद्धति

सीपीएस कन्सन्ट्रेड पॉपी स्ट्रा के अनुसार सरकार किसानों को अफीम फसल उत्पादन के लिए लाइसेंस देती है। किसान अफीम के डोडा चूरा नहीं लगा सकता। डोडे से अफीम लेने का अधिकार किसान को नहीं मिलेगा। सरकार या सरकार की एजेंसी किसान के खेत से अफीम के डोडों को काट लेती है। इसके बदले किसानों को भुगतान किया जाता है। अब तक यह पद्दति विदेशों में होती है। इससे तस्करी पर लगाम लगेगी। 3.7 से अधिक और 4.2 से कम मार्फिन देने वाले किसानों को सीपीएस के तहत 6 आरी के पट्टे मिलेंगे।

तीन खंडों की स्थिति

अफीम खंड- 1 में 157 गांव हैं। इनमें करीब 4 हजार 842 किसानों को अफीम लायसेंस वितरित किए जाएंगे। पिछले साल इनकी संख्या 5950 थी। इस खंड में 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पट्टे दिए जाएंगे।

अफीम खंड- 2 में 136 गांव हैं। इनमें करीब 5 हजार 30 किसानों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। पिछले साल अफीम उत्पादक किसानों की संख्या 6 हजार 216 थी। इस खंड में 2 नवम्बर तक पट्टे वितरित किए जाएंगे।

अफीम खंड- 3 में 237 गांव हैं। इनमे 3 हजार 938 किसानों को लाइसेंस की पात्रता है। पिछले वर्ष इनकी संख्या 5 हजार 4 थी। तृतीय खंड में 31 अक्टूबर तक पट्टे वितरित किए जाएंगे।

20 एकड़ जमीन, 76 लाख शासन से मिले, 5 लाख ग्रामीणों ने किए एकत्र

मप्र में नवाचारों के गांव नवादपुरा में अब आत्मनिर्भर गोशाला

2020 (अगस्त) में काम शुरू हुआ 14 माह में तैयार 200 फीट की गौशाला

300 गाय रह सकेंगे इसलिए 17 एकड़ में लगाए पौधे

मोहिनी डी वर्मा, धार

धार जिले का छोटा-सा गांव नवादपुरा नवाचारों के लिए पहचान बना चुका है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पक्की सड़कें व मकानों पर एक ही रंग और बच्चों के लिए तरणताल जैसी सुविधाओं के बाद अब यहां ऐसी पहली शासकीय गौशाला बनाई गई है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर होगी। हाल ही में गोशाला के शुभारंभ अवसर पर 11 गायों का प्रवेश भी करवाया गया।

परिसर के 17 एकड़ में हरी घास व चरी के मध्य में अमरूद, नींबू, सहजन, खजूर, नारियल, सुपारी के पांच हजार पौधे लगाए गए हैं। दो-तीन साल बाद इनसे आय भी होने लगेगी। गौशाला की गायों के गोबर से दीपक, मूर्तियां, तोरण द्वार और गौ-मूत्र से सैनिटाइजर व अन्य उत्पादन बनाकर बाजार में बेचे जाएंगे। परिसर में ग्रामीण परिवेश नुमा चार काटेज बनाए गए हैं। प्राकृतिक वातावरण के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये काटेज पर्यटकों के लिए आनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इससे होने वाली आय भी गौशाला के संचालन में सहायक होगी। परिसर के मध्य में 10 बाय 200 फीट का मार्ग बना है, जिसके अंत में राधा-कृष्ण का मंदिर होगा। मंदिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालु यहां रहने वाली गायों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे।

सिखाएंगे पर्यावरण संरक्षण का पाठ

गांव के कमल पटेल बताते हैं कि गौशाला में गाय के गोबर व गौमूत्र से 10 तरह के जैविक खाद व दवा बनाई जाएगी। विक्रय करने के साथ यहां आने वाले किसान भाइयों को इसे बनाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण के लिए नक्षत्र वाटिका भी बनाई गई है। इसमें विभिन्ना औषधीय पौधे लगाए गए हैं। परिसर में मियावाकी पद्धति से पौधे रोपे गए हैं।

-कमलनाथ का खरीदा गेहूं केंद्र सरकार ने लेने से किया इंकार

शिवराज ने 1200 करोड़ में बेचा

-72 लाख टन गेहूं समर्थन पर 2019-20 में खरीदा गया था

भोपाल।

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के जिस छह लाख 43 हजार टन गेहूं को सेंट्रल पूल में लेने से मना कर दिया था, उसे प्रदेश सरकार ने लगभग 12 सौ करोड़ रुपए में बेचा है। खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने इस गेहूं की बिक्री की है। तीन लाख टन गेहूं के उठाव के अनुबंध भी हो चुके हैं। यह गेहूं कमलनाथ सरकार के समय में खरीदा गया था। तब सरकार ने किसान समृद्धि योजना प्रारंभ करके किसानों को प्रति क्विंटल 165 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इसे केंद्र सरकार ने बोनस मानते हुए सेंट्रल पूल में लेने से मना कर दिया था। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी जब बात नहीं बनी तो शिवराज सरकार ने इसे नीलाम करने का निर्णय लिया।

छोटे-छोटे समूह बनाए तो मिली अच्छी कीमत

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम पर बढ़ते जा रहे कर्ज के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने छह लाख 43 हजार टन गेहूं को नीलाम करने का फैसला किया। निगम ने पहले दो लाख टन गेहूं नीलाम करने के लिए निविदा निकाली पर शर्तों को लेकर विवाद हो गया और सरकार ने पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके बाद छोटे-छोटे समूह बनाकर गेहूं नीलाम करने का कदम उठाया गया। इस प्रयास को सफलता मिली और औसत एक हजार 875 रुपए प्रति क्विंटल की दर प्राप्त हुई, जो समर्थन मूल्य से अधिक रही। अधिकांश गेहूं का गोदामों से उठाव करने के लिए अनुबंध हो गए हैं। निगम को गेहूं की बिक्री से लगभग एक हजार 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि, इसके बाद भी निगम लगभग साढ़े चार सौ करोड़ रुपए के घाटे में रहेगा, क्योंकि किसान को भुगतान करने के बाद गेहूं के भंडारण, परिवहन सहित अन्य कार्यों में बड़ी राशि व्यय होती है।

यह था विवाद

2019-20 में किसानों से एक हजार 840 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 72 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। खरीद प्रारंभ होने के पहले कमल नाथ सरकार ने किसानों को 165 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। खरीद के दौरान जब सेंट्रल पूल में गेहूं देने की बात आई तो केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति उठाई। दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अनुबंध है कि खरीद के पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिसका बाजार पर विपरीत असर पड़े। प्रदेश सरकार का तर्क था कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि दी जा रही है पर केंद्र सरकार इससे सहमत नहीं हुई।

उज्जैन में सर्वाधिक दो हजार 52 रुपए में बिका

गेहूं की नीलामी में सर्वाधिक दो हजार 52 रुपए प्रति क्विंटल की दर उज्जैन में प्राप्त हुई है। जबकि, सबसे कम एक हजार 629 रुपए की प्रति क्विंटल की दर रीवा में मिली थी। इस निविदा को शासन ने निरस्त कर दिया और अब 12 हजार 80 टन गेहूं की दोबारा नीलामी की जाएगी।

आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के जन्मोत्सव पर सीएम ने कहा-

गोसेवा में लगी संस्थाओं को सम्मानित किया

सरकार और समाज मिलकर गौमाता को बनाएं स्वावलंबी

जबलपुर।

आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौसेवा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौशाला का संचालन अकेले सरकार के वश की बात नहीं है। समाज के साथ मिलकर ही यह काम संभव है। गो माता की हर एक चीज उपयोगी है। इसका यदि सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो खुद ही गौशाला स्वावलंबी हो जाएगी। सीएम ने दयोदय में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राज्य में गो सेवा के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आचार्य भगवन राष्ट्र संत है। वो सिर्फ जैन धर्म के नहीं, बल्कि सबके हैं। उन्होंने आचार्य श्री को आत्मनिर्भरता का प्रेरक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री कई आयामों पर कार्य कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हथकरघा, गौशाला, आयुर्वेद समेत कई कार्य हो रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने जीव दया पुरस्कार भगवन के नाम पर देने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि

गौशाला का काम समाज की बिना भागीदारी के संभव नहीं है। सरकार आखिर कितनी गोशाला बनाएगी? इसलिए जरूरी है कि लोग आगे आकर इस दिशा में काम करे। उन्होंने भरोसा दिया कि गो संरक्षण में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।कहता नहीं करता भी हूं - मुख्यमंत्री ने गौ-संरक्षण के लिए लोगों से गो ग्रास की प्रथा को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि मंच से नेता हूं तो बोल दिया। जो बोलता हूं उसे आत्मसात भी करता हूं। मैं जब पहली दफा मुख्यमंत्री बना था तो अपने साथ सीएम हाउस में दो गाय लाया था। जो बाद में 44 हो गई थी। उन्हें खेत में रखा। बीच में कुछ वक्त मुख्यमंत्री नहीं था। अब चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो फिर दो गाय लाया था। अब उनकी संख्या पांच हो गई है। सुबह पूजन के पश्चात गो शाला में गाय को रोटी और एक पौधा लगाकर ही दिन का कार्य शुरू करता हूं।

धन्य हुआ आचार्य श्री के दर्शन से

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के दर्शन मात्र से धन्य हो गया। आचार्य ज्ञान, करुणा, दया, स्नेह, आत्मीयता, कृपा के सागर हैं। उन्होंने कहा कि जो दूसरों को जीते वो वीर और जो अपने आप को जीते वो महावीर हैं। मानव जीवन सार्थक करना है तो अपने आपको जीतकर जिन बनकर जैन बनना है। कार्यक्रम में गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरि महाराज ने प्रदेश की जनता से गो संरक्षण के लिए गो ग्रास परम्परा को जिंदा रखते हुए प्रतिदिन 10 रुपए गुल्लक में निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की एक करोड़ जनता भी यदि ऐसा करती है तो सालाना 350 करोड़ गौ संरक्षण के लिए जमा हो जाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी एवं जैन समाज के संत मौजूद रहे।

डूब प्रभावित गांवों में दस दिनों से भूकंप के हल्के झटके

आलीराजपुर।

नर्मदा किनारे सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित क्षेत्रों में बीते करीब दस दिन से लगातार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। यह दावा यहां के लोगों का है। उनका कहना है कि कुछ सेकंड के लिए धरती में कंपन महसूस हो रहा है। इससे कई घरों की दीवारों में दरारें भी आ गई हैं। विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि बांध के बैकवाटर के कारण यहां धरती की प्लेटें सरक रही हैं। इससे यहां यह स्थिति संभावित है। डूब प्रभावित क्षेत्र के ग्राम अट्ठा, सिरखड़ी, बड़ी गेंद्रा, उमरठ, अचपई के लोग कहते हैं कि बीते करीब दस दिन से यहां धरती में कंपन महसूस हो रहा है। कभी सुबह तो कभी शाम को एकाएक यहां झटके आ रहे हैं। इससे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। अट्ठा सरपंच गमरसिंह व ग्रामीण हरदासभाई बताते हैं कि प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है। जिला प्रशासन ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। विशेषज्ञ डूब प्रभावित क्षेत्र में पूर्व से ही प्लेटों के सरकने के कारण भूगर्भीय गतिविधि होने की आशंका जाहिर करते रहे हैं। भूगर्भीय हलचल के कारण क्षेत्र में कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। झटके महसूस होने पर लोग अपने घरों को छोड़ बाहर निकल रहे हैं।

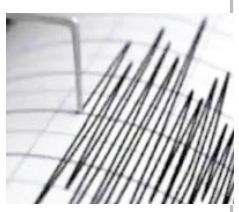

हे भगवान...ये क्या हो गया! अगस्त में बाढ़ और भारी बारिश का कहर झेल चुके जिले के किसान बेमौसम की दूसरी मार से सदमे में

बारिश से उजड़ी 27 हजार हेक्टेयर में खड़ी धान-सरसों की फसल

अगस्त के महीने में बाढ़ और अतिवृष्टि से बर्बादी का दंश झेल चुके जिले के किसानों पर बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी है। रविवार की रात हुई बारिश से जिले में 27 हजार हेक्टेयर रकबे में खड़ी धान और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। हाल ही में बोई गई सरसों की फसल तो बारिश का पानी खेतों में भरने से पूरी तरह गलकर बर्बाद हो गई। जिसकी बोवनी किसानों को दोबारा से करनी पड़ेगी या फिर दूसरी कोई फसल की बोवनी करनी होगी। नुकसान का यह अनुमान कृषि विभाग के फसल नुकसान के प्रारंभिक सर्वे में आया है। फसल नुकसान का यह आंकडा घट-बढ़ भी सकता है। क्योंकि कृषि विभाग और राजस्व विभाग का मैदान अमला अभी खेतो में पहुंचकर फसल नुकसान का सर्वे कर रहा है।

खेमराज मौर्य, शिवपुरी, श्योपुर।

दो माह के भीतर किसानों पर मौसम की यह दूसरी मार पड़ी है। जिस कारण जिले का किसान सदमे में पहुंच गए हैं। यहां बता दें कि जिले में रविवार की रात को हुई तेज बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान खेतों में खड़ी धान और सरसों की फसल को हुआ है।

कृषि विभाग के सूत्रों की माने तो जिले में 45 हजार हेक्टेयर में धान की फसल खड़ी है। जबकि 30 हजार हेक्टेयर में सरसों की बोवनी हो चुकी है। बारिश से करीब 12 हजार हेक्टेयर में खड़ी सरसों की फसल प्रभावित हुई है। ज्यादातर किसानों की सरसों की फसल की बीज खेतों में ही पानी भरने से गल गया है। इसलिए किसानों को सरसों की फसल की दोबारा से बोवनी करनी पड़ेगी। जबकि 15 हजार हेक्टेयर में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिससे धान की फसल का उत्पादन 25 से 30 फीसदी कम होने का अंदेशा है।

154.9
एमएम रिकॉर्ड बारिश

1449
एमएम बारिश औसतन

312
एमएम कराहल में

सर्वे में जुटा मैदानी अमला

कृषि विभाग के प्रारंभिक सर्वे में अभी 27 हजार हेक्टेयर में खड़ी फसल के प्रभावित होने का अनुमान है। लेकिन फसल नुकसान का यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। कारण यह है कि कृषि विभाग का मैदानी अमला अभी राजस्व अमले के साथ खेतो में पहुंचकर बारिश से फसलों को पहुंचे नुकसान का सर्वे कर रहा है। इसकी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद भी फसल नुकसान का सही पता चलेगा और प्रशासन भी तभी पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई करेगा।

बारिश से प्रभावित हुई फसलें

फसल	बोवनी	प्रभावित रकवा
धान	45 हजार	15 हजार
सरसों	30 हजार	12 हजार

नोट-रकवा हेक्टेयर में है।

बारिश से धान और सरसों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। नुकसान का आंकलन करने के लिए हमारी टीमें राजस्व अमले के साथ खेतों में पहुंचकर सर्वे कर रही है। सर्वे रिपोर्ट आने पर ही नुकसान का सही पता चलेगा।

पी गुजरे, उप संचालक,
कृषि विभाग श्योपुर

अक्टूबर में पहली बार बारिश का कहर, 10 घंटे में बरसा 154.9 एमएम रिकॉर्ड पानी

बीते रविवार की रात जिले में 10 घंटे के भीतर 154.9 एमएम रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश कराहल तहसील में 312 एमएम हुई। जिसे मिलाकर अब तक श्योपुर जिले में कुल औसत 1494 एमएम बारिश हो चुकी है, जो श्योपुर के लिए नया रिकॉर्ड बन गया है,क्योंकि इतनी बारिश अभी तक श्योपुर जिले में कभी नहीं हुई, जबकि दूसरा रिकॉर्ड यह भी बन गया है कि अक्टूबर में पहली बार जिले में इतनी बारिश गिरी है। यूं तो मानसून की विदाई हो चुकी है। इसके बाद भी बीते रविवार की रात को पूरे जिले में 154.9 एमएम बारिश हुई है। बताया गया है कि कराहल तहसील में 312 एमएम बारिश हुई है। जबकि श्योपुर तहसील में 137.6, विजयपुर में 86, बड़ौदा में 156 तथा वीरपुर तहसील में 83 एमएम बारिश हुई है।

-जनजातीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह ने की घोषणा

हेरिटेज शराब आदिवासियों को बनाएगी आत्मनिर्भर

आदिवासियों को मिलेगी महुआ से शराब बनाने की इजाजत

भोपाल, संवाददाता

मध्यप्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा से प्रदेश के आदिवासी बाहुलय क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यही नहीं, इससे जनजातीय वर्ग आत्मनिर्भर भी होगा। मप्र में आदिवासियों की आबादी 21 प्रतिशत है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या एक करोड़ 53 लाख है। मप्र में हर पांचवां व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। दरअसल, झाबुआ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार आदिवासियों को महुआ से शराब बनाने की इजाजत देगी। वो यहां जनजातीय सम्मेलन शामिल हुए थे। शिवराज ने कहा कि आदिवासियों को उनकी परंपरा के अनुसार शराब बनाने की छूट दी जाएगी। अभी जो हालत है उसमें कोई आदिवासी अगर शराब बना ले तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। जबकि उन्हें अपनी परंपराओं के पालन और पूजा-पाठ संबंधी गतिविधियों के लिए भी इसकी जरूरत होती है। आदिवासियों को इसकी छूट देने के लिए उनकी सरकार नई नीति लाएगी। फिर आदिवासियों को महुआ से शराब बनाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। अब मप्र सरकार हेरिटेज वाइन पॉलिसी बनाएगी। इसके तहत सरकार अब महुए की शराब बनाकर बेचने की तैयारी कर रही है। आबकारी विभाग ने हेरिटेज मदिरा पॉलिसी तैयार कर ली है। इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस पॉलिसी के पीछे राजस्व बढ़ाने और आदिवासियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि राजस्थान में जोधपुर में 'चंद्रहास' और उदयपुर में 'आशा' ब्रांड की शराब बनाई जाती है। अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी शराब बनाने जा रही है। यह शराब महुआ से बनाई जाएगी और इसे शराब दुकानों पर बेचा भी जाएगा। हालांकि अभी तक शराब के ब्रांड का नाम तय नहीं हो सका है। सरकार महुआ से बनने वाली नई शराब को मप्र के नाम से राज्य के बाहर भेजेगी। इसीलिए पॉलिसी में यह प्रावधान रखा जा सकता है कि इसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा।

कैबिनेट में आएगी पॉलिसी

आबकारी विभाग की इस हेरिटेज मदिरा पॉलिसी को कैबिनेट में लाया जाएगा। इसी पॉलिसी के तहत मप्र की डिस्टलरीज आदिवासी क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों की मदद से शराब बनवाएंगी। सरकार की कोशिश है कि महुआ की शराब से आदिवासी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले।

राजस्व बढ़ाने की कवायद इस पॉलिसी के पीछे राजस्व बढ़ाने की कवायद भी बताई जा रही है। यदि सरकार महुआ की शराब बनाकर बेचती है, तो उससे उसे 300 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिल सकता है। हेरिटेज मदिरा पॉलिसी के साथ ही शराब का उत्पादन, बॉटलिंग और बिक्री की प्रोसेस में सुधार करने का भी प्रस्ताव है। सरकार इससे पहले विलेज टूरिज्म पॉलिसी लेकर आ चुकी है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में स्थित दर्शनीय, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी कड़ी में अब ये हैरिटेज वाइन पॉलिसी है।

पूर्व एपीसीसीएफ ने साझा किया अपना अनुभव, बोले

मध्यप्रदेश सरकार का निर्णय आदिवासियों के लिए लाभकारी

इधर, मप्र के रिटायर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. रामगोपाल सोनी ने 'जागत गांव हमार' से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का महुआ की हेरिटेज शराब बनाने का निर्णय आदिवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। चूंकि आदिवासी समाज अत्यधिक मेहनती है और परंपरागत रूप से वो लोग देशी महुआ की शराब पीते रहे हैं। मैं तो नहीं पीता किंतु एक उदाहरण जरूर दूंगा। उन्होंने बताया कि जब मैं पेंच टाइगर रिजर्व में था तो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म निर्माता और एक फाइनेंसर वहां रुके थे। अंग्रेजी शराब पीते थे और देर से सोकर उठते थे। एक दिन जल्दी उठ गए तो उन्होंने बताया की हमने कल देशी शराब बुलाकर पी थी, जो हालांकि दुर्गंध युक्त थी किंतु इससे सिर भारी नहीं हुआ और बहुत अच्छी थी। दूसरा उदाहरण कैप्टन फोरसिथ का है, जिन्होंने लिखा की अल्मोद जो पचमढ़ी से 10 किमी दूर रोरी घाट से 6 किमी छिंदवाड़ा जिले में है। वहां के लोग देशी शराब बनाते थे, जो आइरिस विसकी जैसी लगती है। आगे उन्होंने कहा की अगर उसकी गंध दूर हो जाए सौंफ डालकर तो उसकी स्वीकार्यता अधिक बढ़ जाएगी। सोनी ने अपना बस्तर का अनुभव साझा करते हुए बताया कि

बस्तर के उत्पादन का मैंने संकलन किया था। सम्पूर्ण बस्तर में उस समय जो महुआ फूल मंडी में आया था उसकी मात्रा 30000 एमटी थी। इसके अलावा कुछ मात्रा वो लोग अपने उपयोग के लिए रख लेते होंगे। किंतु पैसों की कमी से वो 90 फीसदी महुआ फूल बिचौलियों को बेंच देते थे 5 रुपए किलो। बिचौलिए महुआ को उन्हीं गांवों में कच्चे घरों में ही वैज्ञानिक और देशी तरीके से रख देता था। वर्षात तथा ठंड में वही आदिवासी लोग 12 रुपए किलो खरीद कर देशी दारू बनाते थे। आज भी पैसों के अभाव में गरीब आदिवासी महुआ फूल, जो स्टेपल फूड है उसकी डोभरी, लाटा बनाकर खाते हैं, को पहले गर्मी में बेंच देते हैं फिर दो से ढाई गुना कीमत में खरीदकर शराब बनाकर पीते और बेचते हैं। सोनी कहते हैं कि जब बड़े व्यापारी अंग्रेजी शराब बना सकते हैं तो गरीब आदिवासी लोग क्यों नहीं बनाएं। प्रदेश सरकार इसको ब्रांडेड बनाए और उनको इसका लाभ दिलाए। महुआ के बहुत पेड़ जंगल में है जो पूरा तो इक्ट्ठा ही नही कर पाते । वनों में महुआ वन्य प्राणियों का भी उपयोगी फूड है। वन विभाग को चाहिए की रोपण में कुछ प्रतिशत महुआ का भी वृक्ष लगाए। पशु अवरोधक खंती में मेंड़ में दस मीटर की दूरी पर अगर महुआ की गुल्ली ही गड़ा दी जाए, तो बहुत अच्छे पौधे हो जाते हैं, मैने लगवाया था। चूंकि महुआ बहुत अधिक जगह घेरता है, इसलिए इसको निजी भूमि पर कोई नहीं लगाता किंतु वनों में आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा महुआ के बीज का वानस्पतिक घी बनाने में उपयोग होता है, जो पाम ऑयल से अधिक अच्छा है। महुआ की गुल्ली में जो ऊपर छिलकायुक्त पल्प होता है वह मीठा भी होता है उससे भी देसी दारू बन सकती है अभी वह फेंक दिया जाता है।

-मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह की अनूठी पहल

ग्रामीणों को शिक्षित करने हर पंचायत में बनेगी लाइब्रेरी

ग्रामीणों को विकास का पाठ पढ़ाएगी 'जुगाड़ लाइब्रेरी'

मंडला। संवाददाता

जिले की हर ग्राम पंचायत में इन दिनों जुगाड़ से लाइब्रेरी बनाई जा रही है। जुगाड़ भी ऐसा की हर घर की रद्दी कॉपी किताबों को ग्राम पंचायतों में सजाया गया है। ये पहल जिले में मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने की है। जिसका मकसद है, कि जो ग्रामीण नई-नई चीजें पढ़ना और लिखना चाहते हैं, वो यहां आकर आराम से पढ़ और लिख सकते है। दरअसल, मंडला कलेक्टर ने एक नई पहल शुरू की है। जहां जिले में हर रोज एक गाड़ी अब कचरा नहीं किताबों को इकट्ठा कर रही है। गांव-गांव शहर-शहर एक ज्ञान रथ घूम रही है। जो हर घर के रद्दी कॉपी-किताबों का कलेक्शन कर रही है। ये गाड़ी हर घरों से किताबों का भंडार कर नगर पालिका में रख रही है। इसके बाद ये किताबें गांव-गांव और शहर के ग्राम पंचायतों में जाकर एक लाइब्रेरी में रखी जा रही है।

11 से 4 बजे तक पढ़ सकेंगे- इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोग अब हर तरह कि किताबें लाइब्रेरी के माध्यम से 11 बजे से 4 बजे के बीच पढ़ सकते हैं। इतनी ही नहीं इस किताब को अगर कोई घर लेकर जाना चाहता हैं, तो वह लेकर भी जा सकता है। फिर उसे पढ़कर वापिस लौटा सकता है। स्थानीय लोग भी इस पहल में बढ़चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पूरी किताबों को घर आते हुए ज्ञान रथ में दान कर रहे हैं।

सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा

मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि इस पुस्तकालय से सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पुस्तकालय का मकसद ये है कि हर ग्राम में एक ऐसा प्वाइंट बनाया जाए जहां हर ग्रामीण अध्यन कर चर्चा कर सकें ऐसे कई लोग है जो पैसे और सुविधाओं के अभाव में पेपर नहीं खरीद पाते या फिर किताबें नहीं खरीद पाते है। उन्हे अब यहां से फ्री मिलेगा, जिससे ग्रामीणों में विभिन्न सकारात्मक परिचर्चा हो सके। इसके अलावा ये पुस्तकालय महिला ज्ञानलय के रूप में कार्य करेगा। जहां गांव और शहर की शिक्षित महिलाएं बाकी महिलाओं को पढ़ा सके। इसी उद्देश्य के साथ इस पुस्तकालय की शुरूआत की गई है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
रहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-7000141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)